



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2015/वैशाख 15, 1937

No. 147]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2015/VAISAKHA 15, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 1 मई, 2015

सं. टीएमपी/62/2009-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, पारादीप पत्तन न्यास के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/62/2009-पीपीटी

कोरम:

- (i). श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(अप्रैल 2015 के 28वें दिन पारित)

यह मामला पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से सम्बंधित है।

2. पीपीटी का मौजूदा दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएमपी/62/2009-पीपीटी दिनांक 25 मार्च 2011, जिसे 23 मई 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च 2013 तक निर्धारित करता है। यह प्राधिकरण पीपीटी के दरमान की वैधता कई बार विस्तारित कर चुका है; पिछला विस्तार आदेश दिनांक 2 जनवरी 2015 द्वारा 31 मार्च 2015 तक था।

3. पीपीटी ने 2005 दिशानिर्देशों के अधीन 27 अगस्त 2012 को मौजूदा दरमान के संशोधन हेतु अपना प्रस्ताव दाखिल किया था जिसपर विचार-विमर्श किया गया था। प्रस्ताव की आंतरिक रूप से संवीक्षा की गई है और इस मामले में संयुक्त सुनवाई 25 फरवरी 2013 को आयोजित की गई थी।

4.1. जब यह मामला इस प्राधिकरण के अंतिम विचार के लिए तैयार किया जा रहा था, पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 30 अक्टूबर 2013 द्वारा निवेदन किया था कि वित्तीय वर्ष 2012-13 पहले ही समाप्त हो चुका था और वर्ष 2012-13 के लिए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं जिनपर विचार किया जाना है क्योंकि प्रहस्तित किए जाने के लिए अनुमानित कार्गो मिश्रण में बदलाव किया गया है और तेल कार्गो में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 12 अक्टूबर 2013 को भारी चक्रवात की वजह से, पत्तन ने अपनी संपत्तियों को हुए नुकसान उठाए थे जोकि लगभग रु० 82.71 करोड़ अनुमानित किया गया था। पीपीटी ने बताया है कि हुए नुकसानों की पूर्ति के लिए अनुदान प्रदान किए जाने हेतु भारत सरकार को किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाता है तो पीपीटी को यह सुधार लागत अपने आंतरिक संसाधनों से पूरी करनी होगी जिसका इसके आंतरिक संसाधनों पर प्रभाव पड़ेगा।

4.2. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, पीपीटी ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के लिए तीन महीने के समय की मांग की थी। पीपीटी द्वारा बताए गए कारणों से, पत्तन को उसके संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 31 जनवरी 2014 तक का समय दिया गया था। चूंकि प्रस्ताव प्राप्त नहीं

हुआ था, इसलिए पीपीटी को हमारे पत्र दिनांक 17 फरवरी 2014 द्वारा उसका संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने का अनुस्मरण करवाया गया था। पत्तन को उसका संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने की सलाह देते हुए पीपीटी के साथ पत्राचार किया गया था। 30 सितम्बर 2014 तक मौजूदा दरमान की वैधता का विस्तार करते समय, पीपीटी को 2005 के लागू प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन उसका संशोधित प्रस्ताव 31 अगस्त 2014 तक दाखिल करने की दोबारा सलाह दी गई थी। पीपीटी से संशोधित प्रस्ताव की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। अतः, पीपीटी को लागू प्रशुल्क दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए उसका संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने की सलाह दी गई थी।

5.1. इसी बीच, पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने अपने पत्र सं. 8(1)/2014-टीएमपी दिनांक 13 जनवरी 2015 द्वारा "महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015" जारी की गई थी जिसे इस प्राधिकरण द्वारा राजपत्र सं. 30 दिनांक 27 जनवरी 2015 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। नई "महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015" 13 जनवरी 2015 से लागू हुई है।

5.2. एमओएस द्वारा महापत्तन न्यासों के लिए 2015 की नई प्रशुल्क नीति में परिकल्पित प्रशुल्क निर्धारण प्रक्रिया 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट प्रशुल्क निर्धारण पद्धति से काफी भिन्न है। इसलिए, पीपीटी द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव पर 2005 दिशानिर्देशों के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। इसके मद्देनजर, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 13 फरवरी 2015 द्वारा पीपीटी के दरमानों के सामान्य संशोधन हेतु पीपीटी का प्रस्ताव बन्द कर दिया था। पीपीटी को एमओएस द्वारा घोषित 2015 की नई प्रशुल्क नीति के अनुसार संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने की सलाह दी गई है।

5.3. पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा बताया है कि प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 1.5 के अनुसार, टीएमपी को नीति फ्रेमवर्क प्रचालित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने हैं। इसलिए, पीपीटी ने 01 अप्रैल 2015 से लागू किए जाने वाले सामान्य संशोधन प्रस्ताव की तैयारी हेतु स्पष्टीकरण मांगा है।

5.4. हमने हमारे पत्र दिनांक 25 फरवरी 2015 द्वारा पीपीटी को सूचित किया है कि पीपीटी द्वारा तैयार किया जाने वाला नया सामान्य संशोधन प्रस्ताव प्रशुल्क नीति, 2015 के आलोक में तैयार किए जाने की जरूरत है और मसौदा कार्य दिशानिर्देशों पर भी आधारित है तथा प्रस्ताव शीघ्रतम प्रस्तुत करना होगा।

6. प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 1.5 के अनुसार, इस प्राधिकरण ने मसौदा कार्यकरण दिशानिर्देश तैयार किए थे और सभी महापत्तन न्यासों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। प्रशुल्क नीति, 2015 को कार्यान्वित करने के लिए मसौदा कार्यकरण दिशानिर्देश सभी महापत्तन न्यासों से विचार-विमर्श कर तैयार किए जाने हैं। पीपीटी को नई प्रशुल्क नीति, 2015 का अनुसरण करते हुए अपना प्रस्ताव अभी दाखिल करना है। जब पीपीटी से प्रस्ताव प्राप्त होगा उसपर नई प्रशुल्क नीति, 2015 का अनुसरण करते हुए कार्यवाही की जाएगी।

7.1. तथापि, पीपीटी के मौजूदा दरमान की विस्तारित वैधता समाप्त हो चुकी है और नई प्रशुल्क नीति, 2015 के अधीन पीपीटी के दरमान के सामान्य संशोधन के लिए पीपीटी द्वारा दाखिल (किए जाने वाले) प्रस्ताव पर नई प्रशुल्क नीति, 2015 का अनुसरण करते हुए नए सिरे से विचार-विमर्श किया जाएगा और इस प्राधिकरण के अंतिम विचार के लिए मामला तैयार करने में कुछ और समय लगेगा।

7.2. अतः यह प्राधिकरण पीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता इसकी समाप्ति की तारीख से 30 सितम्बर 2015 अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख, जो भी पहले हो, तक विस्तारित करता है।

8. 1 अप्रैल 2013 के बाद की अवधि के लिए पीपीटी को प्रोद्भूत होने वाले अतिरिक्त अधिशेष, यदि कोई हो, का संव्यवहार महापत्तन न्यासों हेतु नई प्रशुल्क नीति, 2015 द्वारा शासित किया जाएगा।

टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./143/2015(36)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 1st May, 2015

No. TAMP/62/2009 – PPT.— In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/62/2009-PPT

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 28th day of April 2015)

This Order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust (PPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the PPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/62/2009-PPT dated 25 March 2011 which was notified in the Gazette of India on 23 May 2011. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2013. This Authority has extended the validity of SOR of PPT on couple of occasions; the last extension being till 31 March 2015 vide Order dated 2 January 2015.

3. The PPT had filed its proposal for revision of the existing SOR on 27 August 2012 under 2005 guidelines which was taken on consultation. The proposal has been internally scrutinized and joint hearing in this case was held on 25 February 2013.

4.1. When the case was being firmed up for final consideration of this Authority, the PPT, vide its communication dated 30 October 2013, submitted that the financial year 2012-13 was already over and the actual figures for the year 2012-13 are available which may have to be considered since the cargo mix estimated to be handled has undergone a change and the oil cargo has increased substantially. Moreover, due to severe cyclone on 12 October 2013, port has suffered damages to its properties which is estimated to be around ₹82.71 crores. The PPT had stated that if its request to Government of India for a grant to restore the damages caused is not considered, the PPT will have to meet the restoration cost from its internal resources which will affect its internal resources.

4.2. In view of the above position, the PPT sought three months' time to submit a revised proposal for general revision of its SOR. For the reasons stated by PPT, the port was allowed time till 31 January 2014 to file its revised proposal. Since the proposal was not received, the PPT was reminded to file its revised proposal vide our letter dated 17 February 2014. Correspondence were exchanged with PPT advising port to file its revised proposal. While extending the validity of the existing SOR till 30 September 2014, the PPT was again advised to file its revised proposal by 31 August 2014 under the applicable tariff guidelines of 2005. The revised proposal from PPT was still awaited. The PPT was, therefore, advised to file its revised proposal following applicable tariff guidelines.

5.1. In the meantime, the Ministry of Shipping (MOS), vide its letter No. 8(1)/2014-TAMP dated 13 January 2015 issued the new "Policy for determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" which was notified in the Gazette of India vide Gazette No. 30 dated 27 January 2015 by this Authority. The new "Policy for determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" has come into effect from 13 January 2015.

5.2. The tariff fixation process envisaged in the new Tariff Policy of 2015 for Major Port Trust by MOS, is significantly different from the tariff fixation method stipulated in the Tariff Guidelines of 2005. Hence, the proposal filed by PPT could not be processed under 2005 guidelines. In view of this, this Authority vide its Order dated 13 February 2015 had closed the PPT proposal for general revision of its Scale of Rates. The PPT has been advised to file a revised proposal in accordance with the new Tariff policy of 2015 announced by the MOS.

5.3. The PPT vide its letter dated 11 February 2015 has stated that as per Clause 1.5 of the Tariff Policy, 2015 TAMP to issue guidelines to operationalise the policy frame work. The PPT has, therefore, sought clarification for preparation of the general revision proposal to be effective from 01 April 2015.

5.4. We have vide our letter dated 25 February 2015 informed the PPT that the new general revision proposal needs to be firmed up by the PPT in the light of the Tariff Policy, 2015 and also based on the draft Working Guidelines and submit the proposal at the earliest.

6. As per Clause 1.5 of Tariff Policy, 2015, this Authority has formulated draft working guidelines and circulated to all Major Port Trusts for their comments. The draft working guidelines to operationalise the Tariff Policy, 2015 is to be firmed up in consultation with all Major Port Trusts. The PPT, is yet to file its proposal following new Tariff Policy, 2015. The proposal when received from the PPT will have to be processed following the new Tariff Policy, 2015.

7.1. The extended validity of the existing SOR of PPT, however expired on 31 March 2015 and the proposal (to be) filed by the PPT for general revision of its Scale Rates under new Tariff Policy, 2015 will have to be taken up for fresh consultation, following the new Tariff Policy, 2015 and it will take some more time for the case to mature for final consideration of this Authority.

7.2. This Authority, therefore, extends the validity of the existing SOR of PPT from the date of its expiry till 30 September 2015 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

8. The treatment of additional surplus, if any, accruing to the PPT for the period beyond 1 April 2013 will be governed by the new Tariff Policy for Major Port Trusts, 2015.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT.-III/4/Exty./143/2015(36)]